भारत सरकार

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 431

उत्तर देने की तारीख 24 जुलाई, 2024 (बुधवार)

2 श्रावण, 1946 (शक)

प्रश्न

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में सड़क और परिवहन अवसंरचना परियोजना

431. श्री बैजयंत पांडाः

क्या **उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास आज की तिथि के अनुसार उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में सड़क और परिवहन अवसंरचना परियोजनाओं की प्रगति के संबंध में अद्यतन जानकारी है; और

(ख) इस क्षेत्र के अंदर और शेष भारत के साथ संपर्क में सुधार करने के लिए की गई विशिष्ट पहलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) और (ख) जी, हां। पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों और विभागों द्वारा कई सड़क और परिवहन अवसंरचना विकास परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

सड़क कनेक्टिविटीः सरकार ने एसएआरडीपी-एनई, भारतमाला-I आदि कार्यक्रमों के माध्यम से क्षेत्र के भीतर तथा पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर कार्यक्रम के माध्यम से शेष भारत के साथ संपर्क में सुधार के लिए विशिष्ट पहल की है। 2024-25 के दौरान मई, 2024 तक पूर्वोत्तर राज्यों में कुल 78 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया है। 2024-25 के दौरान जून, 2024 तक पूर्वोत्तर राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों पर कुल 2,859.00 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं।

हवाई कनेक्टिविटीः 2013 में हवाई अड्डों की संख्या 9 थी, जो 2023 तक बढ़कर 17 हो गई है। पिछले 10 वर्षों में हवाई यातायात में भी 113% की वृद्धि हुई है। नागर विमानन मंत्रालय की उड़ान स्कीम के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों में 194 वैध फिक्स्ड विंग और हेलीकॉप्टर रूट्स आवंटित किए गए हैं, जिससे पर्यटकों और निवेशकों को आकर्षित करने में मदद मिलेगी और व्यापार करने में आसानी होगी।

रेल कनेक्टिविटीः पूर्वोत्तर राज्यों और शेष भारत के साथ रेल संपर्क में सुधार करने के लिए 18 रेलवे अवसंरचना परियोजनाएं (13 नई लाइन, 05 दोहरीकरण), जिनकी कुल लंबाई 1,368 किलोमीटर है और लागत 74,972 करोड़ रुपये है, जो पूर्णतः/आंशिक रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में आती हैं, आयोजना/अनुमोदन/निर्माण चरणों में हैं, जिनमें से 313 किलोमीटर लंबाई चालू हो गई है और जिनपर मार्च 2024 तक 40,549 करोड़ रुपये का व्यय हो चुका है।

जलमार्ग कनेक्टिविटीः पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) ने अपने सागरमाला कार्यक्रम के तहत पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं शुरू की हैं। पिछले 10 वर्षों में 19 नए जलमार्ग जुड़कर पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुल 20 जलमार्ग संचालित हो रहे हैं। असम में कुरुआ, बहारी, धुबरी, गुइजान, घागोर और मटमोरा में 310 करोड़ रुपये की लागत से 6 फेरी टर्मिनलों का विकास यात्रियों की परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करेगा, जिससे परिवहन की वर्तमान बाधाएं कम हो जाएंगी। अंतर्देशीय जल पारगमन एवं व्यापार पर भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल (पीआईडब्ल्यूटीएंडटी) के अंतर्गत जलमार्गों की संख्या 8 से बढ़ाकर 10 कर दी गई है तथा पीआईडब्ल्यूटीएंडटी के अंतर्गत प्रत्येक देश में ग्यारह पड़ाव पत्तन और दो विस्तारित पड़ाव पत्तन घोषित किए गए हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में आईबीपी रूट्स पर 4.7 मिलियन टन माल की आवाजाही हुई।

इसके अतिरिक्त, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न स्कीमों/पैकेजों को कार्यान्वित कर रहा है, जैसे उत्तर पूर्व विशेष अवसंरचना विकास स्कीम - सड़कें (एनईएसआईडीएस-रोड्स), असम के विशेष पैकेज [बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (बीटीसी), दीमा हसाओ स्वायत्त प्रादेशिक परिषद (डीएचएटीसी) और कार्बी आंगलोंग स्वायत्त प्रादेशिक परिषद (केएएटीसी)], और एनईसी (पूर्वोत्तर परिषद) की स्कीमें, जिनके तहत सड़क और परिवहन की परियोजनाएं स्वीकृत की जाती हैं। इन विकासात्मक स्कीमों/पैकेजों के अंतर्गत, शुरूआत से अब तक कनेक्टिविटी परियोजनाओं सहित 23,240.78 करोड़ रुपये की लागत वाली 1,980 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

*****